[श्री ज र्ज फरनेन्डीज़]

"the right of either House of Parliament to set a privileged person at liberty and the right to punish those who make or procure arrests."

यह इस सदन का अधिकार है और इसके तीन केसेज उन्होंने यहां पर साइट किए हैं, ग्रास-गिल्स केस, मिल्स और बर्टन केस जो 72 नम्बर के पन्ने पर दिया हुआ है कि हाउस आफ कामन्स के अपने सदस्य को जब अदालत ने या दूसरे लोगों ने गिरफ्तार किया था तो हाउस आफ कामन्स ने अपने सदस्यों को रिहा करने का हुक्म दिया और उनको रिहा किया गया। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि मेरे यह जो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं इन को आप स्वीकार करें और मधु लिमये जी को तत्काल रिहा करने के लिए आप आदेश दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, या तो इसको आप प्रिविलेज कमेटी को भेज दें या सदन को चर्चा करने का मौका दें, कौन सा तरीका आप अख्त्यार करने जा रहे हैं?

SHRI S. KUNDU (Balasore): This must be discussed.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): One submission to you.......

MR. SPEAKER: Is he supporting Mr. Fernandes?

SHRI S. M. BANERJEE: I only support what Mr. Vajpayee said: either we should get an opportunity to discuss or it should be referred to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: Before any decision is taken, I must give notice to the Government, and they must also give me the facts. I would not give my ruling or anything like that now. I would also like to hear the Government, probably tomorrow or the day after. I have also received a letter from Mr. Limaye straight from the jail. Therefore, I would like to give my careful thought to it.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरा निवेदन है कि जो कुछ श्री फरनेन्डीज ने कहा है उसमें से एक बात साफ़ है कि सदन को जो सूचना दी गई जो मैजिस्ट्रेट से आई उस में और जो गृह मंत्री ने सदन में कहा उस में अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : मुझ को भी साफ होना पड़ेगा, आप को तो साफ हो गया।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वह अभी भी जेल में हैं, तो उनकी रिहाई की बात तो होनी चाहिए। अभी वह दिल्ली में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको सरकार ने खड़ा किया है। तो आप गृह मंत्री से उनको छोड़ने के लिए तो कहिए।

13.09 hrs.

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

ADVISORY COUNCIL OF THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): On behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) (h) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Shri Jagannath Pahadia resigned."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) (h) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Shri Jagannath Phadia resigned."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now we adjourn and meet at 2.00 P.M.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958."

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

14.07-½ hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE AND INDIAN RAILWAYS (AMENDM/NT) BILL

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं । आप आर्डर-पेपरपर देखेंगे कि मेरे प्रस्ताव और इस विधेवक पर बहस एक साथ रखी गई है । लेकिन इस विधेयक पर मेरा एक संशोधन भी है, मैंने रूल 109 के अन्तर्गत एक मोशन भी दिया है—

"That the debate on the Indian Railways (Amendment) Bill be adjourned.".

MR. DEPUTY SPEAKER: He can do that later on, after the Minister has moved the motion. Now he will speak on the resolution.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय-मैं नियमों को लेकर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । यह प्रश्न इस तरह से आया है कि एक तरफ तो आर्डिनेन्स है जिसकी डिसएप्रवल पर मेरा प्रस्ताव है, दूसरी तरफ विधेयक है, जिस पर बहस होनी है, इस पर मेरा मोशन है कि इस बहस को एडजर्न किया जाए, यह मैंने रूल 109 में दिया है, जो कि मेरे प्रस्ताव पर लागू नहीं होता है ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): You can appreciate the difficulty. This resolution seeks to disapprove of the ordinance. The hon. Member would like to condemn the

*Published in Gazette of India Ex-traordinary, Part II, section 2, dated 25-11-68.

**Introduced with the recommendation of the President.